सबगुरु डिजिटल मीडिया प्लेटफार्म
फेसबुक पेज लिंक
https://www.facebook.com/sabgurunews/
वेबसाइट लिंक
https://www.sabguru.com/
यूट्यूब चैनल लिंक
https://www.youtube.com/channel/UCCcLf90UP-prqTinNwqUXZg/
English Article Link:
https://www.sabguru.com/en/the-role-of-dopamine-understanding-the-feel-good-hormone/

SABGURU NEWS

सबगुरु न्यूज

(राष्ट्रीय द्विभाषीय पाक्षिक)

मो.9887907277 Email ID sabgurunews@gmail.com Website https://www.sabguru.com

सम्पादक - विजय सिंह

RNI TITLE CODE NO. RAJBIL27046

खबरों के लिए स्कैन करें

वर्ष 2 | अंक 3 | अजमेर, गुरुवार 25 जुलाई 2024 | मूल्य 5 रुपए | पृष्ठ-4

आमबजट 2024-25

वेतनभोगियों को मानक छूट की राहत, विदेशी कंपनियों पर कर में कमी

नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वर्ष 2024-25 के लिए मंगलवार को प्रस्तुत पूर्ण बजट में वेतनभागी आयकर दाताओं को राहत देते हुए मानक कटौती को 50 हजार रुपए से बढ़ाकर 75 हजार रुपए करने की घोषणा की तथा नई व्यक्तिगत कर व्यवस्था में कुछ बदलाव करने का प्रस्ताव किया। उन्होंने विदेशी कंपिनयों पर कार्पोरेट कर को 40 प्रतिशत से कम कर 35 प्रतिशत करने की भी घोषणा की है। बजट में गैर सूचीबद्ध कंपनियों स्टार्टअप आदि द्वारा शेयरों के आवंटन से जुटाए जाने वाले धन पर एंजल कर को समाप्त करने का बड़ा प्रस्ताव भी किया गया है। यह कर शेयर के अनुमानित बाजार मूल्य से ऊपर की प्राप्त राशि पर लगाया जाता हैं। विदेशी कंपनियों पर कारपोरेट कर दर को 40 प्रतिशत से घटाकर 35 प्रतिशत करने का प्रस्ताव है।

इसी तरह व्यक्तिगत आयकर दरों के संबंध मेंए नई कर व्यवस्था का विकल्प चुनने वालों के लिए दो घोषणाएं है। पहला वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए मानक छूट को 50000 रुपए से बढ़ाकर 75000 रुपए करने का प्रस्ताव है। इसी प्रकारए पेंशनभोगियों के लिए पारिवारिक पेंशन पर कटौती को 15000 रुपए से बढ़ाकर 25000 रुपए करने का प्रस्ताव है। इससे नई कर व्यवस्था में लगभग चार करोड़ वेतनभोगियों और पेंशनभोगियों को लाभ होगा।

सामाजिक सुरक्षा लाभ में सुधार हेतुए नई पेंशन योजना एनपीएस में नियोजनकर्ता द्वारा किए जा रहे योगदान को कर्मचारी के वेतन के 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 14 प्रतिशत करने का प्रस्ताव है। इसी प्रकार, निजी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और उपक्रमों में नई कर व्यवस्था का विकल्प चुनने वाले कर्मचारियों की आय से वेतन के 14 प्रतिशत तक व्यय की कटौती का प्रावधान करने का प्रस्ताव है।सीतारमणन ने प्रत्यक्ष कर संबंधी प्रस्तावों के शुरू में कहा कि आयकर अधिनियम 1961 की व्यापक समीक्षा की जाएगी। धर्मार्थ संस्थाओं के लिए कर में छूट की दो व्यवस्थाओं को मिलाकर एक करने का प्रस्ताव है। इसी तरह अनेक भुगतानों पर पांच प्रतिशत टीडीएस कर पर कटौती की दर को घटा कर दो प्रतिशत टीडीएस दर किया जा रहा है। बजट में ई.कॉमर्स ऑपरेटरों पर टीडीएस दर को 1 प्रतिशत से कम करके 0.1 प्रतिशत करने का प्रस्ताव है। साथ हीए टीसीएस की राशि को वेतन पर कटौती किए जाने वाले टीडीएस की गणना में लाभ दिए जाने का प्रस्ताव है। उन्होंने कहा कि आगे कोई कर निर्धारण निर्धारण वर्ष के समाप्त होने के तीन वर्षों के बाद केवल तभी फिर से खोला जा सकेगा जब निर्धारण वर्ष के समाप्त होने से लेकर अधिकतम पांच वर्षों की अवधि तक कर से छूट प्राप्त आय 50 रुपए लाख या उससे अधिक हो। इसी तरह सर्च छापे संबंधी मामलों में भी दस वर्षों की मौजूदा समय सीमा के स्थान पर छापे के वर्ष से पहले छह वर्ष की समय सीमा करने का प्रस्ताव है। सरकार का कहना है कि इससे कर.अनिश्चितताओं और विवादों में कमी आएगी। बजट में परिसंपत्तियों पर कैपीटल गेन के छूट की सीमा को बढ़ाकर 1.25 लाख रुपए प्रतिवर्ष करने का प्रस्ताव है। अपील में लंबित कतिपय आयकर विवादों के समाधान के लिए कि विवाद से विश्वास योजना 2024 का प्रस्ताव किया गया है। कर प्राधिकरणों उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय में प्रत्यक्ष करों, उत्पाद शुल्क और सेवा कर से संबंधित अपीलों को दायर करने के लिए मौद्रिक सीमाओं को क्रमशः 60 लाख दो करोड़ और पांच करोड़ तक बढ़ाने का प्रस्ताव किया गया है।भारतीय स्टार्ट.अप इकोसिस्टम को प्रोत्साहित करने उद्यमशीलता की भावना को बढ़ावा देने और इनोवेशन को समर्थन देने के लिएए निवेशकों के सभी वर्गों के लिए एंजेल टैक्स को समाप्त करने का प्रस्ताव है। देश में घरेलू क्रूज का संचालन करने वाली विदेशी शिपिंग कंपनियों के लिए एक सरल कर व्यवस्था का प्रस्ताव है।

नई कर व्यवस्था इस प्रकार होगी....

आय	कर
0 से तीन लाख रुपए	00
तीन लाख से सात लाख रुपए	05 प्रतिशत
सात लाख से 10 लाख रुपए	10 प्रतिशत
10 लाख से 12 लाख रुपए	15 प्रतिशत
12 लाख से 15 लाख रुपए	20 प्रतिशत
15 लाख से अधिक	30 प्रतिशत

सोना चांदी होगी सस्ती

नई दिल्ली। सरकार ने सोना और चांदी पर आयात शुल्क को घटाकर 6 प्रतिशत करने का ऐलान किया है जिससे इन दोनों कीमती धातुयें सस्ती हो जाएगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2024.25 के बजट भाषण में सोने, चांदी पर आयात शुल्क घटाकर 6 प्रतिशत करने की घोषणा की।भारत दुनिया में सर्राफ़ा का दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है। ऐसे में सरकार ने सोने और चांदी पर आयात शुल्क 15 प्रतिशत से घटाकर 6 प्रतिशत कर दिया है। विशेषज्ञों ने इससे खुदरा मांग बढ़ने की उम्मीद जताई है। साथ ही तस्करी को कम करने में मदद मिल सकती है। सोने की बढ़ती भारतीय मांग से दुनिया भर में कीमतें बढ़ सकती हैं।

नई निजी आयकर व्यवस्था से बचेंगे 17500 रुपए

- केंद्रीय बजट 2024.25 में नई व्यक्तिगत आयकर व्यवस्था का प्रस्ताव किया गया है जिसमें करदाताओं को 17500 रुपए का लाभ होगा।
- वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को संसद में पेश केंद्रीय बजट में कहा कि नई कर व्यवस्था से सरकार को 7000 करोड़ रुपए के राजस्व का नुकसान होगा और चार करोड़ वेतनभोगियों और पेंशनभोगियों को लाभ होगा।
- केंद्रीय बजट के अनुसार व्यक्तिगत आय पर मानक कटौती 50 हजार रुपए से बढ़ाकर 75 हजार रुपए कर दी गयी है। इससे निजी करदाता को 17500 रुपए का लाभ होगा। इसके अलावा परिवार पेंशन में कटौती की सीमा 15 हजार से बढ़ाकर 25 हजार कर दी गई है।

बजट रूपया आया और गया

नई दिल्ली। वित्त वर्ष 2024.25 के केंद्रीय बजट में एक रुपये में आय और व्यय का ब्यौरा इस प्रकार है

रूपया आया

उधारी और अन्य देयताएं से 27 पैसे आयकर से 19 पैसे जीएसटी एवं अन्य कर से 18 पैसे निगम कर से 17 पैसेए कर भिन्न प्राप्तियां नौ पैसे सीमा शुल्क से चार पैसे और ऋण भिन्न पूंजीगत प्राप्तियां से एक पैसा।

रूपया गया

करों एवं शुल्कों में राज्य का हिस्सा में 21 पैसे ब्याज भुगतान में 19 पैसेएकेन्द्रीय क्षेत्र योजना रक्षा और सब्सिडी पर पूंजीगत परिव्यय को छोड़कर 16 पैसेए अन्य व्यय नौ पैसेए वित्त आयोग और अन्य अंतरण पर नौ पैसेए रक्षा पर आठ पैसे सब्सिडी पर छह पैसे और पेंशन पर चार पैसे।

बच्चों के लिए नई पेंशन योजना वात्सल्य

नई दिल्ली। सरकार ने बच्चों के लिए नई पेंशन योजना एनपीएस वात्सल्य की घोषणा की है जिसमें माता.पिता और अभिभावक को अंशदान करना होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज संसद में पेश केन्द्रीय बजट 2024.25 में बच्चों के लिए एक नई पेंशन योजना वात्सल्य की घोषणा की। इस पेंशन योजना में माता-पिता और अभिभावक अंशदान करेंगे। वयस्कता की आयु होने परए इस योजना को सहज रूप से एक सामान्य एनपीएस खाते में बदला जा सकेगा।सीतारमण ने यह भी घोषणा की कि एनपीएस की समीक्षा के लिए गठित समिति ने अपने काम में पर्याप्त प्रगति की है। उन्होंने इस बात पर संतोष व्यक्त किया कि केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए संयुक्त परामर्शदात्री तंत्र की राष्ट्रीय परिषद के कर्मचारियों ने रचनात्मक दृष्टिकोण अपनाया है।उन्होंने कहा कि एक ऐसा समाधान निकाला जाएगा जिससे महत्वपूर्ण मुद्दों का समाधान निकल सके और साथ ही आम जनता के हितों की सुरक्षा के लिए राजकोषीय दूरदर्शिता भी बनाई रखी जाएगी।

बजट में एक करोड़ शहरी आवास के लिए दस लाख करोड़ रुपए का प्रावधान

नई दिल्ली। वित्त वर्ष 2024-25 के केंद्रीय बजट में आवास योजना शहरी 2.0 के तहत दस लाख करोड़ रुपए के निवेश से शहरी गरीबों और मध्यम वर्गीय आय वाले परिवारों के लिए एक करोड़ आवासों को पूरा करने का प्रावधान किया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को वित्त वर्ष 2024-25 का बजट पेश करते हुए कहा कि पीएम आवास योजना के तहत शहरी आवास के विकास के लिए 10 लाख करोड़ का प्रावधान किया गया है। शहरी आवास योजना 2.0 के तहत सरकार एक करोड़ लोगों को आवास देगी। उन्होंने कहा कि औद्योगिक कामगारों के लिए पीपीपी मोड में डोरमेट्री जैसे आवास वाले किराए के मकानों की सुविधा प्रदान की जाएगी।

वित्त मंत्री ने कहा कि 100 बड़े शहरों के लिए जल आपूर्ति सीवेज ट्रीटमेंट और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन परियोजनाओं एवं सेवाओं को बढ़ावा दिया जाएगा। सरकार ने अगले पांच साल में प्रत्येक वर्ष चुनिंदा शहरों में 100 साप्ताहिक बाजार के विकास में सहायता के लिए एक योजना की परिकल्पना की है।

वित्त मंत्री ने प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण और

शहरी क्षेत्रों में तीन करोड़ अतिरिक्त आवासों के निर्माण की घोषणा की गई है जिसके लिए आवश्यक धनराशि का प्रबंध बजट में किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के अंतर्गत 10 लाख करोड़ रुपए के निवेश से एक करोड़ शहरी गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों की घर संबंधी जरूरतों को पूरा किया जाएगा। इसमें अगले पाँच वर्षों में 2ण्2 लाख करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता शामिल होगी।उन्होंने कहा कि औद्योगिक कामगारों के लिए वीजीएफ सहायता और एंकर उद्योगों की प्रतिबद्धता के साथ पीपीपी मोड में डोरमेट्री जैसे आवास वाले किराए के मकानों की सुविधा प्रदान की जाएगी। उन्होंने कहा कि इसके अलावाए अधिक उपलब्धता के साथ दक्ष और पारदर्शी किराए के आवास बाजारों के लिए समर्थकारी नीतियां तथा विनियम भी बनाए जाएंगे। वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में कहा कि 30 लाख से अधिक जनसंख्या वाले 14 बड़े शहरों के लिए कार्यान्वयन और वित्तपोषण रणनीति के साथ आवागमन उन्मुखी विकास योजनाएं तैयार की जाएंगी।

उन्होंने कहा कि सडक पर रेहड़ी.पटरी लगाने वाले दैनिक विक्रेताओं के जीवन में बदलाव लाने के उद्देश्य से पीएम स्वनिधि की सफलता के आधार पर अगले पांच साल में प्रत्येक वर्ष चुनिंदा शहरों में 100 साप्ताहिक बाजार या स्ट्रीट फूड हब के विकास में सहायता के लिए एक योजना की परिकल्पना की गई है।

सम्पादकीय

अर्थव्यवस्था को तीव्र गति एवं महाशक्ति बनाने वाला बजट

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के तीसरे कार्यकाल का प्रथम सम्पूर्ण बजट वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रस्तुत किया उनकी ओर से प्रस्तुत यह बजट एक मौलिक सोच एवं दृष्टि से दुनिया में भारतीय अर्थव्यवस्था को एक चमकते सितारे के रूप में स्थापित करने एवं सुदृढ़ आर्थिक विकास के लिये आगे की राह दिखाने वाला है। संभावना है कि इस बजट में समावेशी विकास, वंचितों को वरीयता, नौकरीपेशा का थोड़ी राहत, बुनियादी ढांचे में निवेश, पर्यटन को बढ़ावा, आदिवासी उन्नयन,क्षमता विस्तार, हरित एवं कृषि विकास, महिलाओं एवं युवाओं की भागीदारीए मोदी के नये भारत.सशक्त भारत.विकसित पर बल दिया गया है।

वित्त मंत्री ने सरकार की 9 प्राथमिकताओं .खेती में उत्पादकता और मजबूती बढ़ानाए रोजगार और स्किल डेवलपमेंटए मानव संसाधन का समावेशी विकास और सामाजिक न्याय, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज, अर्बन डेलपमेंट, एनर्जी सिक्योरिटीए इंफ्रास्ट्रक्चर, इन्नोवेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, नेक्स्ट जेनरेशन रिफॉर्म्स का ऐलान किया हैए जो देश को आत्मनिर्भर बनाने की रफ्तार को भी गति देगा। बजट में जहां बिहार और आंध्र प्रदेश को विशेष योजनाओं से जोड़ा गया है वहीं महंगाई को नियंत्रित करने की मंशा साफदिखाई दी है। विकासए स्टार्टअप और रोजगार सृजन के कार्यक्रमों पर विशेष ध्यान दिया गया है। यह बजट देश को न केवल विकसित देशों में बल्कि इसकी अर्थव्यवस्था को विश्व स्तर पर तीसरे स्थान दिलाने के संकल्प को बल देने में सहायक बनेगा। सातवीं बार बजट प्रस्तुत कर वित्तमंत्री सीमारमण ने पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई द्वारा स्थापित रिकॉर्ड को तोड़ दिया है जिन्होंने वित्त मंत्री के रूप में पांच वार्षिक बजट और एक अंतरिम बजट पेश किया था। सशक्त एवं विकसित भारत निर्मित करनेए उसे दुनिया की आर्थिक महाशक्ति बनाने और अर्थव्यवस्था को तीव्र गति देने की दृष्टि से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा मंगलवार को लोकसभा में प्रस्तुत आम बजट इसलिए विशेष रूप से उल्लेखनीय है क्योंकि मोदी सरकार ने देश के आर्थिक भविष्य को सुधारने पर ध्यान दिया न कि लोकलुभावन योजनाओं के जरिये प्रशंसा पाने अथवा कोई राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश की है। राजनीतिक हितों से ज्यादा देशहित को सामने रखने की यह पहल अनूठी हैए प्रेरक है। अमृत काल का विजन तकनीक संचालित और ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था का निर्माण करना हैए जो इस बजट से पूर्ण होता हुआ दिखाई देता है। इस बजट में मध्यम वर्ग को लम्बे अन्तराल के बाद 7 लाख रुपये तक की कुल कमाई करने वालों को बड़ी राहत दी है। नए टैक्स रिजीम के तहत स्टैंडर्ड डिडक्शन की लिमिट 50 हजार रुपये से बढ़ाकर 75 हजार रुपये कर दिया गया है। साथ ही नए टैक्स रिजीम में टैक्स स्लैब में बदलाव किया गया है। बजट में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स में भी कुछ अहम बदलाव करने का एलान किया है। मौजूदा नियमों के तहत एक वित्त वर्ष के दौरान अधिकतम 1 लाख रुपये तक के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर कोई टैक्स नहीं लगता है। इस लिमिट को बढ़ाकर 1.25 लाख रुपये सालाना कर दिया गया है।

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा नवाचार अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के लिये बुनियादी अनुसंधान और प्रोटोटाइप विकास के लिए अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान कोष की स्थापना की घोषणा की। वाणिज्यिक स्तर पर निजी क्षेत्र द्वारा संचालित अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए 1 लाख करोड़ रुपये का वित्तपोषण पूल भी बनाया जाएगा। मोबाइल फोन और मोबाइल पीसीबीएस तथा मोबाइल चार्जर पर बीसीडी को घटाकर 15 प्रतिशत करने का प्रस्ताव किया गया है। वित्तीय घाटा 2024-25 तक सकल घरेलू उत्पाद का 4.9 प्रतिशत रहने का अनुमान है। लक्ष्य घाटे को 4.5 प्रतिशत से नीचे पहुंचाने का लक्ष्य है। 25000 ग्रामीण बस्तियों को सभी मौसमों के अनुकूल सड़कें प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना चरण 4 का शुभारंभ किया जाएगा। कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास बनाए जाएंगे। छात्रावासों और क्रेच के माध्यम से कार्यबल में महिलाओं की अधिक भागीदारी को बढ़ावा दिया जाएगा। सरकार समग्र विकास के लिए राष्ट्रीय सहयोग नीति लाएगी। घरेलू संस्थानों में उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख तक के ऋण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने का भी प्रस्ताव है। इस वर्ष शिक्षा रोजगार और कौशल विकास के लिए 1.48 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

माउंट आबू घूमने आए गुजराती सैलानी की हत्या, 4 आरोपी अरेस्ट

माउंट आबू। राजस्थान में पर्वतीय पर्यटन स्थल माउंट आबू घूमने आए गुजरात के सैलानी की मारपीट करके हत्या करने के आरोप में पुलिस ने गुजरात में बनासकांठा क्षेत्र के चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है।पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार ने मंगलवार को बताया कि गत 15 जुलाई को गुजरात से आए मंगाभाई ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी कि वे परिवार के सात लोगों के साथ माउंट आबू घूमने आए थे।

नक्की झील में नाव से घूमने के बाद वे वापस रवाना हुए तो सात घूम के पास उसके भांजे साहिल की वहां मौजूद दो लोगों से कहासुनी हो गई जिसके कुछ ही देर बाद तीन लोग मोटरसाइकिल से आए और उन्होंने उनपर जानलेवा हमला कर दिया। जिससे साहिल गंभीर रूप से घायल हो गया। वे उसे अस्पताल ले गए जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

उन्होंने बताया कि इस पर पुलिस ने गहन जांच पड़ताल की और सीसीटीवी की जांच के बाद आरोपियों की पहचान कर ली। बाद में पुलिस दल गुजरात के बनासकांठा क्षेत्र पहुंचा जहां अलग स्थानों से त्रिवेन्द्र कुमार उर्फटीवा, राहुल गरासिया,जयेश चौहान और मुकेश गरासिया को हिरासत में लिया गया। उन्हें माउंट आबू थाने लाया गया जहां पूछताछ में उन्होंने घटना को अंजाम देना स्वीकार किया।

समाज के हर वर्ग के लिए उज्ज्वल भविष्य लाएगा आम बजट -मोदी

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आम बजट 2024.25 को समाज के हर वर्ग के लिए बेहतर अवसर नई ऊर्जा एव उज्ज्वल भविष्य लाने वाला करार दिया है और कहा है कि यह बजट भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक ताकत बनाने की प्रक्रिया में उत्प्रेरक का काम करेगा विकसित भारत की एक ठोस नींव रखेगा।मोदी ने लोकसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा मंगलवार को पेश किया गया वित्त वर्ष 2024-25 के आम बजट की सराहना करते हुए कहा कि देश को विकास की नई ऊंचाई पर ले जाने वाले इस महत्वपूर्ण बजट के लिए मैं सभी देशवासियों को बधाई देता हूं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एवं उनकी पूरी टीम बहुत.बहुत बधाई की पात्र है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये बजट समाज के हर वर्ग को शक्ति देने वाला है। ये देश के गांव, गरीब, किसान को समृद्धि की राह पर ले जाने वाला बजट है। पिछले 10 वर्षों में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। ये जो नव मध्य वर्ग बना है ये बजट उनके सशक्तिकरण की निरंतरता का बजट है। ये नौजवानों को अनगिनत नए अवसर देने वाला बजट है।उन्होंने कहा कि इस बजट से शिक्षा और कौशल को नया विस्तार मिलेगा। ये मध्य वर्ग को नई ताकत देने वाला बजट है। ये जनजातीय समाज, दलितों और पिछड़ों को सशक्त करने की मजबूत योजनाओं के साथ आया है। इस बजट से महिलाओं की आर्थिक भागीदारी सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। इस बजट से छोटे व्यापारियों, सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्यमों ;एमएसएमई को प्रगति का नया रास्ता मिलेगा। बजट में विनिर्माण एवं बुनियादी ढांचे पर बहुत फोकस है। इससे आर्थिक विकास को नई गति मिलेगी।

प्रधानमंत्री ने कहा कि रोजगार और स्वरोजगार के अभूतपूर्व अवसर बनाना ये हमारी सरकार की पहचान रही है। आज का बजट इसे और सुदृढ़ करता है। देश और दुनिया ने उत्पादकता लिंक इन्सेंटिव योजना की सफलता देखी है। अब इस बजट में सरकार ने रोज़गार लिंक इन्सेंटिव योजना की घोषणा की है। इससे देश में करोड़ों-करोड़ों नए रोजगार बनेंगे।इस योजना के तहतए जीवन में पहली नौकरी पाने वाले युवा की पहली तनख्वाह हमारी सरकार देगी। स्किल डेवलपमेंट और उच्च

शिक्षा के लिए मदद हो या फिर 1 करोड़ नौजवानों को इंटर्नशिप की योजनाए इससे गांव केए गरीब के मेरे नौजवान साथी मेरे बेटे-बेटी देश की टॉप कंपनियों में काम करेंगेए उनके सामने संभावनाओं के नए द्वार खुलेंगे।मोदी ने कहा कि हमें हर शहर हर गांव हर घर उद्यमी बनाना है। इसी उद्देश्य से बिना गारंटी के मुद्रा लोन की सीमा को 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपए किया गया है। इससे छोटे कारोबारियों विशेष रूप से महिलाओं, दलित, पिछड़े और आदिवासी परिवारों में स्वरोजगार को बल मिलेगा। इस बजट में एमएसएमई के लिए आसान ण बढ़ाने वाली नई योजना का ऐलान किया गया है।विनिर्माण एवं निर्यात ईकोसिस्टम को हर जिले तक ले जाने के लिए बजट में अहम घोषणाएं की गई हैं। ये बजट हमारे स्टार्टअप्स के लिए नवान्वेषण ईकोसिस्टम के लिए ढेर सारे नए अवसर लेकर आया है। अंतरिक्ष केन्द्रित आर्थिकी को बढ़ावा देने के लिए 1000 करोड़ रुपये का कोष हो एंजेल टैक्स हटाने का फैसला होए ऐसे कई सारे कदम इस बजट में उठाए गए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि रिकॉर्ड पूंजीगत आवंटन अर्थव्यवस्था को गति देने वाली ताकत बनेगा। 12 नए औद्योगिक क्षेत्रए देश में नए सैटलाइट शहरों का विकास और 14 बड़े शहरों के लिए पारगमन योजनाओं से देश में नए आर्थिक हब विकसित होंगे और बहुत बड़ी संख्या में नए रोज़गार बनेंगे। उन्होंने कहा कि आज रक्षा निर्यात रिकॉर्ड स्तर पर हैं।इस बजट में रक्षा क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाने के लिए अनेक प्रावधान किए गए हैं। आज पूरी दुनिया में भारत के प्रति आकर्षण बढ़ा है। और भारत में पर्यटन के क्षेत्र में नई संभावनाएं बनी हैं। पर्यटन क्षेत्र गरीब और मध्यम वर्ग के लिए कई अवसर लेकर आता है। इस बजट में पर्यटन क्षेत्र पर भी विशेष बल दिया गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार ने पिछले 10 साल में ये सुनिश्चित किया है कि गरीब और मध्यम वर्ग को लगातार करों से राहत मिलती रहे। इस बजट में भी आयकर में कटौती और मानक कटौती में वृद्धि का बहुत बड़ा फैसला लिया गया है। स्रोत पर कर ;टीडीएस के नियमों को भी सरल किया गया है। इन कदमों से हर करदाता को अतिरिक्त बचत होने वाली है।

मोदी ने कहा कि इस बजट का एक बहुत बड़ा फोकस देश के किसान है। अन्न भंडारण के लिए दुनिया की सबसे बड़ी स्कीम के बाद अब हम सब्ज़ी उत्पादन क्लस्टर बनाने जा रहे हैं। इससे छोटे किसानों को सब्ज़ियों.फल, अन्य उपज के लिए नए बाजार मिलेंगे और बेहतर दाम मिलेंगे। हमारे मध्यम वर्ग के लिए फल.सब्जियों की उपलब्धता बढ़ेगी और परिवार के लिए पोषण भी सुनिश्चित होगा। कृषि क्षेत्र में भारत का आत्मनिर्भर बनना समय की मांग है। इसलिए दलहन, तिलहन की पैदावार बढ़ाने के लिए किसानों को मदद की घोषणा की गई है। उन्होंने कहा कि देश में गरीबी समाप्त होए गरीब का सशक्तिकरण होए इस दिशा में भी आज के बजट में प्रमुख घोषणाएं की गई हैं। गरीबों के लिए तीन करोड़ नए घर बनाना तय हुआ है। जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान पांच करोड़ आदिवासी परिवारों को मूलभूत सुविधाओं से जोड़ेगा। इसके अलावा ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 25 हजार नए ग्रामीण क्षेत्रों को हर मौसम में अनुकूल सड़कों से जोड़ा जाएगा।उन्होंने कहा कि भारत का विकास की नई ऊंचाइयों पर चढ़ना पूर्वी भारत की प्रगति से जुड़ा है। इस क्षेत्र में विकास सुनिश्चित करने के लिए हम आधुनिक राजमार्गों और परिवर्तनकारी जल और बिजली परियोजनाओं सहित मजबूत बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध हैं। ऐसा करके हम पूर्वी भारत की विशाल क्षमता को उजागर करेंगे जिससे पूरे देश में विकास और समृद्धि आएगी।

मोदी ने कहा कि आज का बजट नए अवसर नई ऊर्जा लेकर आया है। ये ढेर सारे नए रोजगार स्वरोजगार के अवसर लेकर आया है। ये बेहतर तरक्की और उज्ज्वल भविष्य लेकर आया है। यह बजट भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक ताकत बनाने की प्रक्रिया में उत्प्रेरक का काम करेगा विकसित भारत की एक ठोस नींव रखेगा।

बजट में बिहार तथा आंध प्रदेश को सौगात

नई दिल्ली। वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने 2024-25 के बजट में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार में महत्वपूर्ण घटक जनता दल-यू तथा तेलुगु देशम पार्टी ;तेदपा को खुश करने लिए बिहार तथा आंध्र प्रदेश को विशेष सौगात दी है। सीतारमण ने लोकसभा में बजट 20024-25 पेश करते हुए मंगलवार को कहा कि आंध्र प्रदेश को 15 हजार करोड़ तथा बिहार के लिए 47 हजार करोड़ रुपए के पैकेज देने का प्रावधान किया गया है। बिहार तथा आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग लंबे समय से की जा रही है और अब राजग सरकार के महत्वपूर्ण सहयोगी जद.यू बिहार को तथा तेदपा आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा देने की

मांग कर रहे हैं।वित्त मंत्री ने कहा कि बिहार में सड़क, बिजली और रेलमार्ग का जाल बिछाया जाएगा और इसके लिए बजट में राज्य को 26 हजार करोड़ रुपए देने का प्रावधान किया गयाा है जिसके तहत एक्सप्रेस.वे पावर प्लांट, मेडिकल कॉलेज और महाबोधि कोरिडॉर के निर्माण का ऐलान किया गया है। इसके अलावा नए मेडिकल कॉलेज और एयरपोर्ट को बनाने का भी घोषणा की गई है। साथ ही वैशाली. बोधगया एक्सप्रेसवे पटना.पूर्णिया एक्सप्रेस.वे को ग्रीन सिग्नल मिल गया है। साथ ही केंद्र सरकार गंगा पर दो नए पुल भी बनाएगी। उन्होंने कहा कि बिहार में भागलपुर जिले के पीरपैंती में 2400 मेगावाट के पावर प्लांट समेत 21 हजार 400 करोड़ रुपए की पावर परियोजना बनाई जाएगी।

सूबे में चार नए एक्सप्रेस.वेए गंगा नदी पर एक पुल के साथ ही गया में विष्णुपद कॉरिडोर बनाने का एलान किया। वित्तमंत्री ने आंध्र प्रदेश को भी तोहफा दिया है और कहा कि पुनर्गठन के वक्त किए गए सारे वादे पूरे किए जाएंगे। आंध्र प्रदेश के लिए लगभग 15 हजार करोड़ का पैकेज दिया जाएगा।

ख्वाजा मोईनुद्दीन हसन चिश्ती का 813वां उर्स 31 दिसम्बर से

अजमेर। राजस्थान में अजमेर के सूफी संत ख्वाजा मोईनुद्दीन हसन चिश्ती का

813वां सालाना उर्स नये हिजरी संवत 1446 के रजब माह यानी 31 दिसंबर 2024 से शुरू होकर सात जनवरी 2025 तक भरेगा।

देश.दुनियां से आने वाले जायरीनों की सुविधा के लिए खादिमों की ओर से उर्स की तारीखों के साथ अकीदतमंदों को सूचना भेजने का काम शुरू कर दिया गया है ताकि आशिकाना-ए-ख्वाजा अपनी सहूलीयत से उर्स में अजमेर आने का कार्यक्रम बना सकें। सालाना उर्स रजब महीने के चांद से शुरू होता है। प्रस्तावित कार्यक्रम में 30 दिसंबर को चांदरात पर चांद दिखाई देने पर 31 दिसंबर से उर्स शुरू होगा और इसी दिन दरगाह स्थित जन्नती दरवाजा छह दिनों के लिए खोला जाएगा। दरगाह के महफिल खाने में महफिल होगी। ख्वाजा साहब के आस्ताने पर गुस्ल की धार्मिक रस्म भी होगी। तीन जनवरी 2025 को जुम्मे की नमाज और सात जनवरी को कुल और छठी की फातहा होगी। 10 जनवरी को बड़े कुल की रस्म के साथ उर्स सम्पन्न हो जाएगा।खादिमों ने अपनी ओर से प्रस्तावित कार्यक्रम के जरिये उर्स में शरीक होने के लिए अकीदतमंदों को आमंत्रित किया है। उल्लेखनीय है कि समय पर चांद की शाहदत के समाचार कहीं से नहीं मिले तो सभी धार्मिक रस्में एवं उर्स का आगाज अगले दिन यानि एक जनवरी 2025 से होगा।गरीब नवाज के सालाना उर्स में प्रधानमंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री एवं कई राजनेताओं के साथ पड़ौसी मुल्क पाकिस्तान की चादर भी पेश किए जाने की परम्परा है।

बारां में दो बसों की टक्कर से 2 लोगों की मौत, 8 घायल

बारां। राजस्थान में बारां जिले में मंगलवार को झालावाड़ रोड ओवरब्रिज पुलिया आमापुरा पर गायों को बचाने के प्रयास में दो बसों की भिड़ंत होने से दो लोगों की मौत

हो गई जबकि आठ अन्य घायल हो गए। पुलिस ने बताया कि नाहरगढ़ की ओर से अनुराधा ट्रेवल्स कंपनी की एक बस बारां आ रही थी। इसी दौरान झालावाड़ रोड ओवर ब्रिज पर गायों को बचाने के प्रयास में चालक ने लाइन बदली इसी दौरान पीछे से तेज गति से आ रही बस उससे टकरा गई। टक्कर लगने से आगे जा रही बस पलट गई।उन्होंने बताया कि बस पलटने से क्रेन मंगवाई गई और यात्रियों को निकाला गया। इस घटना में नरेश खंगार और मुकेश प्रजापति की मौके पर ही मौत हो गई जबकि दिनेश गौतम 50 सुरेंद्र सिंह 32 नितेश सुमन ;21 बाबूलाल सुमन ;42 गुड्डी बाई जगन्नाथी बाई 55 और रविंद्र नागर 34 घायल हो गए। जिन्हें अस्पताल पहुंचाया गया।कलेक्टर रोहिताश्व सिंह तोमर ने घटना पर चिंता जताते हुए कहा कि सड़क से आवारा पशुओं को हटाने के लिए सख्ती के साथ कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए निगरानी बढ़ाई जाएगी और आवारा पशुओं को पकड़कर गौशाला भिजवाया जाएगा। फिलहाल में घायलों का अस्पताल में इलाज किया जा रहा है।

कनाडा में एक और हिंदू मंदिर में तोड़फोड़ सांसद ने की कार्रवाई की मांग

ओटावा। कनाडा में अलबर्टा प्रांत कह राजधानी एडमॉन्टन में एक हिंदू मंदिर में मंगलवार को तोडफोड़ की गई और उन पर घृणित भित्तिचित्र बनाए गए। यह घटना हाल ही में कनाडा में हिंदू प्रतिष्ठानों पर हुए हमलों की शृंखला को आगे बढ़ाती है।कनाडा के सांसद चंद्र आर्य ने सोशल मीडिया एक्स पर बीएपीएस स्वामीनारायण मंदिर को विरूपित किए जाने पर अपनी चिंता व्यक्त की। उन्होंने लिखा कि पिछले कुछ वर्षों के दौरान ग्रेटर टोरंटो एरिया, ब्रिटिश कोलंबिया और कनाडा के अन्य स्थानों में हिंदू मंदिरों को घृणित भित्तिचित्रों के साथ नष्ट किया जा रहा है। ऐसी घटनाओं को भड़काने वाले चरमपंथी तत्वों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए बहुसांस्कृतिक मुद्दों पर अपनी वकालत के लिए जाने जाने वाले लिबरल सांसद ने इस बात पर प्रकाश डाला कि सिख फॉर जस्टिस के गुरपतवंत सिंह पन्नून ने पिछले साल सार्वजनिक रूप से हिंदुओं को भारत वापस जाने के लिए कहा था। खालिस्तान समर्थकों ने ब्रैम्पटन और वैंकूवर में घातक हथियारों की तस्वीरें लहरा कर भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा

गांधी की हत्या का सार्वजनिक रूप से जश्न मनाया था।उन्होंने जोर देकर कहा कि जैसा कि मैं हमेशा से कहता रहा हूं खालिस्तानी चरमपंथी नफरत और हिंसा की अपनी सार्वजनिक बयानबाजी से आसानी से बच जाते हैं। उन्होंने मंदिर की क्षतिग्रस्त दीवार की एक तस्वीर के साथ आग्रह करते हुए अपनी पोस्ट समाप्त की एक टूटे हुए रिकॉर्ड की तरह मैं फिर से कनाडाई कानून प्रवर्तन एजेंसियों से इस मुद्दे को गंभीरता से लेने का आह्वान करता हूंए इससे पहले कि ये बयानबाजी हिंदू.कनाडाई लोगों के खिलाफ भौतिक कार्रवाई में तब्दील हो जाए।

तोड़ी गई मंदिर की दीवार पर लिखा है कि प्रधानमंत्री मोदी सांसद आर्य हिंदू आतंकवादी कनाडा विरोधी हैं। पिछले साल नवंबर में एक वकालत संस्था कनाडा.इंडिया फाउंडेशन ने देश के राजनेताओं से अपनी चुप्पी तोड़ने और बहुत देर होने से पहले कट्टरपंथियों पर लगाम लगाने के लिए कहा था। कनाडाई राजनेताओं और मीडिया ने हालांकि इस खतरे को नजरअंदाज कर दिया।स्थिति के जवाब में उन्होंने एक खुले पत्र में कहा था कि हमें इस बात से और भी निराशा हुई है कि हमारे नेताओं ने इस गंभीर मुद्दे पर पूरी तरह से चुप्पी साध रखी है। आतंकवाद और खतरों से निपटने के लिए यह चयनात्मक दृष्टिकोण इस दुनिया को सुरक्षित जगह नहीं बनाएगा।

हाल के दिनों में तोड़े गए हिंदू मंदिरों में मिसिसॉगा में राम मंदिर, रिचमंड हिल में विष्णु मंदिर टोरंटो में बीएपीएस स्वामी नारायण मंदिर, सरे में लक्ष्मी नारायण मंदिर शामिल हैं। इन हमलों को धर्म की स्वतंत्रता पर हमले के रूप में देखा जाता है और एक खतरनाक प्रवृत्ति माना जाता है। वकालत संस्था ने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि चरमपंथियों ने आम हिंदुओं को भी निशाना बनाना शुरू कर दिया है और उन्हें कनाडा छोड़ने के लिए कहा है।

डेढ़ साल से धरने पर बैठा कार्तिक भील का परिवार मुख्यमंत्री से मिला

सिरोही। पंचायती राज मंत्री ओटाराम देवासी ने कार्तिक भील के पिता कपूराराम को मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा से मुलाकात करवाई। करीब डेढ़ साल से चल रहे सिरोही मुख्यालय पर कलेक्ट्रेट में यह परिवार अपनी मांगों को लेकर धरना दे रहा था।मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कार्तिक भील के पिता कपूराराम की मांगों को सुना व उनको न्याय दिलवाने का आश्वासन दिया। साथ ही उनके पुश्तैनी मकान का पट्टा देने व आर्थिक मदद का भरोसा दिलाया।मंत्री देवासी ने बताया कि तत्कालीन कांग्रेस सरकार में कार्तिक भील प्रकरण हुआ था। राजस्थान की गहलोत सरकार ने कार्तिक भील के परिवार वालों को न्याय दिया नहीं दिलवाया ना ही उनकी जायज मांगों को माना। इसके चलते पूरे परिवार के साथ पिता कपूराराम धरने पर बैठ गए। इसके बाद भी सिरोही के तत्कालीन निर्दलीय विधायक संयम लोढ़ा और ना ही तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने न्याय दिलाया।भाजपा जिला मीडिया प्रभारी रोहित खत्री ने बताया कि 19 नवंबर 2022 की आठ लोगों ने बाइक सवार कांतिलाल उर्फ कार्तिक भील व उसके साथी के

साथ मारपीट की। जिसके बाद उसकी मौत हो गई। मौत की सूचना मिलते ही आदिवासीए दलित समाज में आक्रोश फैल गया था। दो दिसंबर की दोपहर बाद से परिजनों के साथ समाज ने सिरोही कलेक्ट्रेट में डेरा डाल दिया था।कार्तिक के पिता कपूराराम भील ने बताया कि उनके शिवगंज कस्बे कि पुस्तैनी मकान से उन्हें राजनीति दबाव से खदेड़ना चाहते हैं। मेरे परिवार के लोगों पर जुड़े मुकदमा दर्ज कर जेल भेजा था। हमारे साथ लम्बे समय से अन्याय व अत्याचार हो रहा। सरकार हमारे साथ न्याय करें।

वकील के साथ मारपीट के विरोध में अधिवक्ताओं का प्रदर्शन

अजमेर। राजस्थान में अजमेर के क्रिश्चियनगंज थाना क्षेत्र में एक अधिवक्ता के साथ हुई मारपीट के मामले में बुधवार को अधिवक्ताओं ने अतिरिक्त जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर प्रदर्शन किया और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की।अजमेर जिला बार एसोसिएशन के सचिव राजेश यादव के नेतृत्व में अधिवक्ता उपखंड अधिकारी ;सिटी कार्यालय पहुंचे जहां उन्होंने हमलावरों को गिरफ्तार करने की मांग की। हमलावर इसी कार्यालय में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत है।

सचिव राजेश यादव ने बताया कि पीड़ित अधिवक्ता महिपाल सिंह से आरोपी जय किशन सोनी ने अभद्र व्यवहार करके उनसे हाथापाई की। महिपाल सिंह एक अन्य शख्स से हुए विवाद में बीच बचाव कर रहे थे।

Punjab Government Provides Tricity Metro Depot with 50 Acres, Opening the Door for Better Urban Mobility

The Punjab government has announced the allocation of 50 acres of land for the construction of a depot for the Chandigarh Tricity Metro project. This strategic land grant represents a major milestone in the development of the metro system, which aims to provide a modern and efficient public transportation solution for the city and its surrounding areas.Tricity Metro on the horizon: Infrastructure development in Tier 2 cities at full swingâ ‹The allocated land will serve as the site for the depot, which is crucial for the maintenance and operation of the metro trains.

This development is expected to streamline the implementation of the metro project, facilitating better connectivity and reducing traffic congestion in Tricity and its neighbouring regions. The establishment of the depot will ensure the smooth functioning of the metro system, contributing significantly to the projects overall success.The Chandigarh Tricity Metro project is a visionary public transportation initiative aimed at providing efficient, reliable, and eco-friendly urban mobility solutions. By enhancing connectivity, reducing traffic congestion, and creating job opportunities, the metro system is poised to significantly improve the quality of life in Tricity and its neighbouring regions.

The project encompasses state-of-the-art metro trains, advanced infrastructure, and seamless integration with existing transportation networks. It is set to become a cornerstone of Tricitys urban landscape, supporting the citys sustainable growth and development for years to come.

केन्द्रीय बजट में विकसित भारत 2047 की रूपरेखा तैयार -भजनलाल शर्मा

जयपुर। राजस्थान की मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने केन्द्रीय बजट 2024-25 का स्वागत करते हुए कहा है कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि का प्रभावी रोडमैप इसमें तैयार किया गया है।शर्मा ने बजट पर अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि यशस्वी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में कृषि, रोजगार, सामाजिक न्याय, नवाचार, ऊर्जा, सुरक्षा बुनियादी ढांचे सहित 9 प्राथमिकताओं के साथ पेश इस बजट से भारत का विश्व की पांचवीं अर्थव्यवस्था से तीसरी अर्थव्यवस्था बनने का मार्ग प्रशस्त होगा। यह बजट 140 करोड़ देशवासियों एवं आठ करोड़ राजस्थानियों की आशाओं और आकांक्षाओं को पूरा करने वाला साबित होगा। उन्होंने केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला

सीतारमण को क्रांतिकारी और ऐतिहासिक बजट प्रस्तुत करने के लिए बधाई देते हुए कहा कि इससे प्रत्येक भारतीय के जीवन में सकारात्मक बदलाव आएगा। उन्होंने कहा कि इस बजट में गरीब, युवा, महिलाए, किसान सहित सभी वर्गों के लिए कल्याणकारी कदम उठाए गए हैं। इस बजट में गरीबों को संबल दिया गया हैए मध्यम वर्ग को मजबूत किया गया है तथा देश की अर्थव्यवस्था को तेजी से विकसित करने का मंत्र दिया गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि बजट में युवाओं को रोजगार और कौशल प्रशिक्षण से जोड़ने के लिए दो लाख करोड़ रुपएए महिला सशक्तीकरण को गति देने के लिए तीन लाख करोड़ रुपए कृषि क्षेत्र के लिए एक लाख 52 हजार करोड़ रुपए तथा ग्रामीण विकास के लिए दो लाख 66 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान विकास की नई इबारत लिखेगा। मजबूत आधारभूत ढांचे के विकास के लिए बजट में जीडीपी के 3.4 प्रतिशत का प्रावधान किया गया है।शर्मा ने कहा कि इस कल्याणकारी बजट में गरीब और मध्यम वर्ग की आवश्यकताओं का विशेष रूप से ध्यान रखा गया है। ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में तीन करोड़ गरीबों और मध्यम वर्ग का घर का सपना पूरा हो सकेगा। उन्होंने कहा कि बजट में नई कर प्रणाली के अंतर्गत आयकर में छूट मानक कटौती की सीमा 50 हजार से बढ़ाकर 75 हजार रुपए करने जैसे प्रावधान कर मध्यम वर्ग और वेतनभोगियों को बड़ी राहत प्रदान की गई है।मुख्यमंत्री ने कहा कि सीमा शुल्क की दरों में कमी किए जाने से कैंसर की दवाईयों, मोबाइल फोन, सोलर सैल और पैनलों की लागत में कमी आएगी।

उन्होंने कहा कि केन्द्रीय बजट की इन सभी घोषणाओं से आपणो अग्रणी राजस्थान के संकल्प को मजबूती मिलेगी और आने वाले समय में विकसित भारत.विकसित राजस्थान का लक्ष्य प्राप्त होगा।

केन्द्रीय बजट से राजस्थान को हाथ लगी केवल निराशा - अशोक गहलोत

जयपुर। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री एवं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत ने केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा संसद में पेश किए गए बजट को दिशाहीन बताते हुए कहा है कि इससे राजस्थान को केवल निराशा हाथ लगी है।गहलोत मंगलवार को केंद्रीय बजट पर अपनी प्रतिक्रिया में यह बात कही। उन्होंने कहा कि ऐसा लगा कि राजनैतिक कारणों से केन्द्र सरकार ने केवल आंध्र प्रदेश एवं बिहार को ही पूरे देश का बजट सौंप दिया हो।उन्होंने कहा कि भौगोलिक एवं सामाजिक रूप से हमारे राजस्थान को विशेष पैकेज की आवश्यकता थी परन्तु पूरे बजट भाषण में राजस्थान का नाम तक नहीं आया जबकि पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान तथाकथित डबल

इंजन की सरकार से डबल विकास के भ्रामक दावे के बगैर प्रधानमंत्री का कोई भाषण समाप्त नहीं होता था। गहलोत ने कहा कि हमें आशा थी कि केन्द्र सरकार इस बजट में पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना ;ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा देगी एवं ईआरसीपी के लिए विशेष फंड मिलेगा लेकिन केन्द्र सरकार ने ईआरसीपी पर भी कोई घोषणा ना कर राजस्थान के हितों के साथ खिलवाड़ किया है।उन्होंने कहा कि पहले भाजपा सरकार का वादा दो करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष का था परन्तु अब पांच साल में एक करोड़ इंटर्नशिप एवं पांच हजार रुपए महीने देने की घोषणा बजट में की गई है।उन्होंने कहा कि महंगाई को काबू करने के लिए इस बजट में कोई उपाय नहीं किए गए हैं। ना तो पेट्रोल व डीजल पर कोई टैक्स कम किया गया और ना ही रसोई गैस सस्ती की गई। राजस्थान में हमारी सरकार ने 500 रुपए में गैस सिलेंडर दिया। जब राजस्थान राज्य ऐसा कर सकता है तो केन्द्र सरकार ऐसा क्यों नहीं कर सकती। उन्होंने कहा कि पूरे बजट भाषण को पढ़ने के बाद जनता निराश है। ऐसा दिशाहीन बजट देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने में शायद ही कामयाब हो।

एक अगस्त को रिक्त हो जाएगा राजस्थान लोकसेवा आयोग अध्यक्ष का पद

अजमेर। राजस्थान में राजस्थान लोकसेवा आयोग ;आरपीएससी का अध्यक्ष पद एक अगस्त को रिक्त हो जाएगा। वर्तमान अध्यक्ष संजय श्रोत्रिय 62 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेंगे। लिहाजा नियमानुसार कार्यकाल समाप्त होने पर वह स्वतः दायित्व से मुक्त हो जाएंगे। आयोग के सूत्रों के अनुसार श्रोत्रिय ने 16 फरवरी 2022 को आयोग के अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया था। सरकार के नियमों के मुताबिक अधिकतम छह वर्ष अथवा 62 वर्ष की आयु पूरी होने पर पद छोड़ना होता है। इस लिहाज से आयोग के अध्यक्ष पद पर उनका अन्तिम कार्यदिवस एक अगस्त रहेगा। वह आयोग के वरिष्ठ सदस्य को दायित्व सौंप कर पदमुक्त हो जाएंगे।

लोकसेवा आयोग में सदस्यों का पहले ही टोटा है। सरकार नए सदस्यों की नियुक्ति नहीं कर रही है और अध्यक्ष की रवानगी भी तय है। सरकार जल्द किसी नए अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं करेगी तो आयोग के कामकाज के साथ परीक्षाओं और साक्षात्कार जैसे महत्वपूर्ण कार्यों पर विपरीत असर पड़ेगा।अजमेर में आयोग मुख्यालय पर अब डॉ. संगीता आर्य, मंजू शर्मा, कर्नल केसरी सिंह राठौड़, प्रो. अय्यूब खान, केसी मीना बतौर सदस्य कार्य सम्भाल रहे हैं। एक सदस्य डॉ. जसवंत सिंह राठौड़ का करीब डेढ़ महीने पहले निधन हो चुका हैए जबकि एक अन्य सदस्य बाबूलाल कटारा पेपरलीक प्रकरण में संलिप्तता के आरोप में निलंबित है। आयोग का कार्य सुचारु एवं निर्बाध गति से चलाने के लिए सरकार को पूर्णकालिक अध्यक्ष एवं नए सदस्यों की नियुक्ति को प्राथमिकता देनी होगी।

समाचार भेजने और विज्ञापन हेतु व किसी अन्य जानकारी के लिए सम्पर्क करें:-

मो. +91 9887907277, 7737385114

Email ID sabgu-runews@gmail.com

अजमेर-6/12बी ब्लॉक हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी पंचशील अजमेर 305001, राज.

जयपुर-D8, गोवर्धन कॉलोनी मोहन मार्ग, विवेक विहार मेट्रो स्टेशन के पास जयपुर 302019, राज.

तीन संतान होने का तथ्य छुपाने वाला निर्दलीय पार्षद बर्खास्त

किशनगढ़/अजमेर। राजस्थान में अजमेर जिले की किशनगढ़ नगर परिषद के निर्दलीय पार्षद को तीन संतान होने के बावजूद चुनाव लड़ने के आरोप में स्वायत्त शासन विभाग ने बर्खास्त कर दिया है।आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि राज्य स्वायत्त शासन विभाग के निदेशक एवं संयुक्त सचिव सुरेश कुमार ओला ने मंगलवार को आदेश जारी करके वार्ड संख्या 57 के पार्षद किशनलाल गुर्जर को चुनाव लड़ने के अयोग्य मानते हुए बर्खास्त कर दिया है।ओला ने पार्षद किशनलाल गुर्जर के विरुद्ध प्राप्त शिकायत की जांच में बच्चों की संख्या की गलत जानकारी देकर चुनाव लड़ने की पुष्टि होने पर उक्त आदेश जारी किए।

विवाहिता 4 माह के पुत्र के साथ ट्रेन के आगे कूदी दोनों की मौत

अजमेर। राजस्थान में अजमेर के अलवरगेट थाना क्षेत्र से गुजर रही मदार रेलवे लाइन पर एक विवाहिता अपने चार माह के बेटे के साथ रेलगाड़ी के आगे कूद गईए जिसमें दोनों की मौत गई।अजमेर जीआरपी थाना पुलिस और अलवरगेट थाना पुलिस ने मौके पर पहुंच कर दोनों शवों को कब्जे में लिया और शवों को जवाहरलाल नेहरु चिकित्सालय के शवगृह में रखवाया। पुलिस ने बताया कि मृतका की पहचान जगदम्बा कालोनी निवासी प्रियंका चौरसिया ;24 के रूप में की गयी है। मृतका की गोद में चार माह का पुत्र थाए जिसके साथ ही उसने ट्रेन के आगे छलांग लगा दी।उन्होंने बताया कि प्रथमदृष्टया ये बात सामने आई है कि मृतका का अपने पति और मां के साथ स्कूटी चलाने की बात लेकर झगड़ा भी हुआए जिससे वह नाराज होकर घर से निकल गई। घटना सोमवार रात 12 बजे बाद की बताई जा रही है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है।

स्वत्वाधिकारी, प्रकाशक विजय सिंह ने मुद्रक किशन गुप्ता द्वारा इंडिया ऑफसेट प्रिंटर्स 419 ब्रह्मपुरी, जयपुर रोड से मुद्रित करवाकर कार्यालय 6/12 बी ब्लॉक हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी पंचशील, अजमेर (राज.) से प्रकाशित किया। सम्पादक- विजय सिंह मो. 9887907277 (सभी विवादों का न्याय क्षेत्र अजमेर रहेगा)